भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4510
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
29 श्रावण, 1947 (शक)

घरों में मोबाइल या टेलीफोन कनेक्शन

4510. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीएएमएस और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास अपने घरों में मोबाइल या टेलीफोन कनेक्शन हैं और क्या सरकार ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की निगरानी करने पर यह पाया है कि शहरी क्षेत्रों में 92.4 प्रतिशत लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में 83.9 प्रतिशत लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, तथापि आंकड़ों के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि मोबाइल फोन का उपयोग इतना सार्वभौमिक नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों, अब तक प्राप्त परिणामों और उन पर स्वीकृत और खर्च की गई निधि का विशेषकर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस) आयोजित किया। सीएएमएस 2022-23 से पता चलता है कि लगभग 94.2% ग्रामीण और 97.1% शहरी परिवारों के पास मोबाइल या टेलीफोन कनेक्शन हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 83.9% ग्रामीण और 92.4% शहरी परिवारों ने मोबाइल फोन का उपयोग करने की क्षमता की सूचना दी। इसके अलावा, अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण की तिथि से पहले के तीन महीनों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 91.7% परिवारों ने सक्रिय सिम कार्ड वाले मोबाइल फोन का उपयोग करने की सूचना दी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी-मार्च 2025 के दौरान एक व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: दूरसंचार (सीएमएस:टी) आयोजित किया गया था। सीएमएस:टी के निष्कर्षों से पता चलता है कि लगभग 94.5% ग्रामीण परिवारों और 96.7% शहरी परिवारों के पास मोबाइल या टेलीफोन कनेक्शन थे। हालाँकि सीएमएस:टी रिपोर्ट में व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग करने की क्षमता को संकलित नहीं किया गया था, फिर भी सर्वेक्षण की तिथि से पहले के अंतिम तीन महीनों के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 82.9% और शहरी क्षेत्रों में 91.0% था।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में पूरी वयस्क जनसंख्या शामिल है। इस व्यापक वर्ग में, 15-24 वर्ष की आयु के युवा समूह में 2022-23 और 2025 के बीच मोबाइल फोन के उपयोग में वृद्धि देखी गई है।

सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले तीन महीनों के दौरान 15-24 आयु वर्ग में मोबाइल फोन का उपयोग		
सर्वेक्षण	ग्रामीण	शहरी
सीएएमएस, 2022-23	92.6	95.3
सीएमएस: टी, 2025	96.9	97.3

(ख): देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने और दूरदराज के गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई परियोजनाएं और पहलें शुरू की हैं। इन सरकारी वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) देश की ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। शेष गैर-जीपी गाँवों को उनकी संबंधित जीपी से माँग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है। जून 2025 तक, देश में भारतनेट परियोजना के तहत 13,01,193 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं ।

(ii) देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न लक्षित मोबाइल परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। 4जी सैचुरेशन और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत, जून 2025 तक देश में 21,748 मोबाइल टावर चालू कर दिए गए हैं।

(iii) अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह को उच्च गति इंटरनेट/डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (2312 किमी) के बीच और मुख्यभूमि (कोच्चि) तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह (1869 किमी) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) परियोजनाएं क्रमशः 10.08.2020 और 03.01.2024 को चालू की गई हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने द्वीपसमूहों में मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य उच्च गति डेटा/इंटरनेट सेवाओं को तेज़ी से शुरू करने में मदद की है।

(iv) विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत, सरकार ने 30.06.2025 तक तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम सहित 36,328.79 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध

30.06.2025 तक देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल/टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन), दूरसंचार विभाग से राज्यवार/योजनावार स्वीकृत/व्यय/वितरित धनराशि

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**स्वीकृत/व्यय/वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)**
1	अंडमान और निकोबार	2150.19
2	आंध्र प्रदेश	1951.44
3	असम	786.46
4	बिहार	890.19
5	छत्तीसगढ	1932.05
6	केंद्रीय रूप से वितरित	9087.21
7	गुजरात (दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव	1010.46
8	हरियाणा	178.89
9	हिमाचल प्रदेश	534.20
10	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	563.58
11	झारखंड	1911.21
12	कर्नाटक	913.24
13	केरल	660.28
14	लक्षद्वीप	839.28
15	मध्य प्रदेश	2237.88
16	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	1757.74
17	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	1093.21
18	पूर्वोत्तर -II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,	1538.34
19	ओडिशा	1724.12
20	पंजाब	1005.50
21	राजस्थान	817.83
22	तमिलनाडु	456.22
23	तेलंगाना	348.06
24	उत्तर प्रदेश	1113.95
25	उत्तराखंड	451.47
26	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	375.78
	कुल योग	**36328.79**

*****